

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत गरियाबंद ज़िला का चयन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले का चयन हुआ है। ज़िले का चयन लघु वनोपजों के उत्पादन, संग्रहण और इनकी गुणवत्ता को देखते हुए किया गया है।

प्रमुख बंदि

- इस संबंध में आयोजित कार्यशाला में वनमंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि ज़िले में पछिले वर्ष 26 हज़ार क्वटिल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। इससे संग्रहकों को 15 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है।
- उन्होंने बताया कि संग्रहण के पश्चात् वनधन केंद्रों में प्रसंस्करण का सिस्टम बनाया गया है। ज़िले में संजीवनी केंद्रों के माध्यम से इसका विक्रय किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 3 हज़ार क्वटिल चर्रिंजी का संग्रहण किया गया है।
- कार्यशाला में कलेक्टर नलिेश क्षीरसागर ने कहा कि ज़िले में लाख, चर्रिंजी, सरई बीज का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। यहाँ के सरई बीजों का वदिशों में भरपूर मांग है। ज़िले में मनी फूड पार्क और प्रसंस्करण केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है।
- ज़िला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि बहिन अंतर्गत ज़िले में 8 हज़ार 500 समूह गठित किये गए हैं, जो अलग-अलग गतविधियों के माध्यम से आय अर्जति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 241 महिला सदस्यों का चयन किया गया है, जिनके लिये 60 लाख रुपए उद्योग वभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत व्यक्तगत नविशक को परियोजना लागत का 35 परतशित की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए पूंजीगत अनुदान मल्लिगा। स्वयं सहायता समूहों के परतसदस्यों को अधिकतम 40 हज़ार रुपए की पूंजी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कसिान उत्पादक संगठन को 35 परतशित की दर से पूंजी अनुदान दिये जाएंगे।